

Rm
du
10/11/17

माननीय राजस्वमंडल मध्य प्रदेश वालियर

=====

पुनरीक्षण संख्या/-

वर्ष 2017

न/निगरानी/टीकमगढ/भू-स/2018/0697

1- परम रजक तनय मेरमा रजक

2/-सरमना अहिरवार तनय बुनुआ अहिरवार

निवासीयान ग्राम ककरवाहा उपतहसील बडागांव धसान

तहसील व जिला टीकमगढ MPRO ----- आवेक

बनाम

रहीश यादव तनय शिखरयाल यादव निवासी ग्राम पहाडी

उपतहसील बडागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ MPRO

===== अनावेक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 MP प्रो मूड राठ सं 1959

मुक्तिल निर्णय एवं आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल बडागांव धसान

तहसील व जिला टीकमगढ MPRO दिनांक 8-6-2016 एवं 29-6-2016

जो कि फ्रण क्रमांक 29/अ-12/2015-016 में पारित किया गया ।

महोदय,

आवेक अपनी पुनरीक्षण याचिका में सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह कि फ्रण के तहत स्लेप में इस फ्रार बताये गये है कि अनावेक ने खसरानम्बर 1236, 1237, 1243 की भूमि का सीमांकन कराने हेतु कार्यवाही की गयी जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा फ्रण पंजीबद्ध कर सीमांकन की कार्यवाही करायी गयी और दिनांक 8-6-2016 को मौका स्थल पर सीमांकन व नापतोल की कार्यवाहीकी जानाबताया गया जिसमें सीमांकन के दौरान खसरा नम्बर 1237 के अंश कवा 0-202 हे 0 पर अपीलार्थी परम का कब्जा पाया गया जिसमें बीर है एवं खसरानम्बर 1236 के अंश कवा पर अपीलार्थी सरमना का कब्जा पाया गया अपीलार्थी क द्वारा सहमति दी गयी और उसके उपरांत अपीलार्थीगण द्वारा मौका पर लिखित में आपत्ति पेश की गयी । उसके उपरांत आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिस आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी विधिसम्मत निराकरण हेतु प्रस्तुत की जा रही है :-

आधार


=====

1/- यह कि उक्त सीमांकन कार्यवाही के समय सही ढंग से नापतोल नहीं की गयी है और अपीलार्थीगण की जमीन के अंश भाग को उ अनावेक क क की भूमि बताकर अपीलार्थीगणका अनधिकृत कब्जाबताया गया है फिर भी अपीलार्थी क ने सहमति दी थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/697

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव तह0 व जि0 टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 08.06.2016 एवं 29.06.2016 के विरुद्ध दिनांक 27.01.2018 को इस न्यायालय विलंब से पेश की गई है, जो कि अवधि वाह्य है। अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवधि वाह्य निगरानी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.06.2016 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की जांच कार्यवाही एवं निराकरण हेतु दिनांक 29.06.2016 नियत की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त नियत दिनांक को यह कहते हुए कि वरिष्ठ न्यायालय को जांच करने के लिए पत्र जारी करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, अनावेदक की आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	